सहकारिता विभाग में आईटी सम्बंधी कार्य

विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस स्थापित किये जाने की दिशा में विभागीय वेब-पोर्टल ई-कोआपरेटिव्स (www.mpsc.mp.nic.in/ecooperatives) का संचालन किया जा रहा है. इस पोर्टल के फलस्वरूप न सिर्फ विभाग के अनेक कार्यों का निष्पादन अपेक्षाकृत द्रुत गति से हुआ है, कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता स्थापित हुई है, वहीं वेब-पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित विवरण अनुसार पहचान प्राप्त हुई हैः

- वर्ष 2012-13 का सी.एस.आई. निहिलेन्त अवार्ड (Appreciation category)
- वर्ष 2014 व वर्ष 2015 का ORDER–OF-MERIT Skoch Award for being among Best eGovernance Projects.
- वर्ष 2015 का eINDIA – Certificate of Recognitions Award
- वर्ष 2016-17 में सी.एस.आई. निहिलेन्त अवार्ड (Appreciation category)

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भोपाल के माध्यम से तैयार कराये गये विभागीय वेब-पोर्टल ई-कोआपरेटिव्स के माध्यम से निम्नलिखित की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हैः

- विभाग से संबंधित सभी हितधारकों (stakeholders) को G2C, G2G एवं G2E सेवाओं की प्रदायता
- विभागीय गतिविधियों की जानकारियों के आनलाईन संप्रेषण एवं प्रवाह
- नागरिक केन्द्रित इंटरफेस

पोर्टल ई-कोआपरेटिव्स पर उपलब्धा सेवाऐंः

G2C सेवायें

- सहकारी सोसायटी के पंजीयन हेतु आनलाईन आवेदन की सुविधा
- आवेदन की निर्णय प्रक्रिया आनलाईन
- प्रदेश की गृहनिर्माण सहकारी सोसायटियों की शिकायत हेतु जनसामान्य को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
- सहकारी संस्थाओं द्वारा पंजीयक को सहकारी अधिनियम की धारा 56(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की आॅनलाईन प्रस्तुति

- उपरोक्त दस्तावेजों की मोबाईल रजिस्ट्रेशन पर एसएमएस अलर्ट के साथ पब्लिक शेयरिंग
- प्रदेश की सहकारी सोसायटियों की सामान्य जानकारियां जनसाधारण को निशुल्क ऑनलाइन उपलब्ध
- विभाग में सोसायटियों के अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार के पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक आवेदकों से पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र आनलाईन आमंत्रित व आनलाईन प्रोसेसिंग
- प्रदेश के कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण खातों व फसल बीमा आदि की जानकारी को एसएमएस के माध्यम से प्रदाय किये जाने हेतु डेटा प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ। कुल 31.82 लाख कृषक पंजीकृत व 24.29 लाख कृषकों के दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति में ऋण खातों की प्रविष्टी पूर्ण

G2G सेवायें

- विभाग में ई-फाईल ट्रैकिंग सिस्टम लागू किये जाने हेतु पोर्टल तैयार
- देश की गृहनिर्माण सहकारी सोसायटियों की शिकायतों के निराकरण हेतु आॅनलाईन मानीटरिंग की व्यवस्थायें
- प्रदेश की सहकारी संस्थाओं की जानकारी, कोर्ट केसेज, स्थापना सम्बंधी मामले तथा मासिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु विभिन्न विभागीय गतिविधियों की जानकारी
- सहकारी ट्रिब्यूनल पूर्णतः आनलाईन. विभाग के अन्य न्यायालयों को आईटी एनेबल्ड् किये जाने का कार्य प्रारंभ
- विभागीय आश्वासनों का आॅनलाईन रजिस्टर
- पोर्टल के माध्यम से समस्त विभागीय कार्यालयों को पत्रों का प्रेषण एवं सम्बंधित अधिकारी को एसएमएस प्रेषण

G2E सेवायें

- विभागीयकर्मियों के लिये ई-सर्विस बुक
- समस्ती विभागीय सेवायुक्तों के लिये पोर्टल के माध्यम से शासकीय दस्तावेजों के प्रेषण हेतु ‘‘ई-संकलन’’ नामक सुविधा
- समस्त विभागीय सेवायुक्तों को सक्षम अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से एसएमएस प्रेषण की सुविधा